

an>

Title: Need to expedite interlinking of river projects in Dindori Parliamentary Constituency in Maharashtra.

श्री हरिश्चन्द्र चव्हाण (दिंडोरी): मेरा संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी महाराष्ट्र के नासिक जिले का एक भाग है। इस संसदीय क्षेत्र में किसान परिवार खेती-बाड़ी और वनों पर निर्भर है। इस क्षेत्र में कई नदियाँ हैं परन्तु किसानों को इन नदियों से सिंचाई के लिए आवश्यकतानुसार पानी नहीं मिला पा रहा है। कई सालों से मेरा संसदीय क्षेत्र सूखाग्रस्त रहा है। गत वर्ष बेमौसम वर्ष से किसानों को करोड़ों रुपये का नुकसान उठाना पड़ा। मेरे संसदीय क्षेत्र के नांदगांव, येवला, चांदवड, मालेगांव, निफाडा देवका, सुरगाण पेठ आदि तहसीलों में किसानों के लिए सिंचाई सुविधा का अभाव है। मेरे संसदीय क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था बनाये रखने के लिए कुछ नदियों को जोड़ने का कार्य शुरू करने के लिए कई वर्षों से बैठक एवं विचार किया गया जिसमें पार-तापी-नर्मदा नदियों के जोड़ने से वार्षिक सिंचाई 2.32 लाख हैक्टेयर एवं जल से विद्युत पैदा करने का प्रस्ताव है। दूसरा नदी सम्पर्क दमनगंगा-पिंजाल का है जिससे 895 एमसीएम घरेलू एवं औद्योगिक आपूर्ति होने की संभावना है। पार-तापी-नर्मदा एवं दमनगंगा-पिंजाल नदियों को जोड़ने का डीपीआर और साध्यता रिपोर्ट पूरी हो गई है और वर्तमान सरकार नदियों को जोड़ने के कार्य को प्राथमिकता दे रही है जिसे कम पानी वाली नदियों को अधिक पानी वाली नदियों के साथ जोड़ा जा सके जिससे कम पानी वाली नदियों को बराबर पानी मिलेगा और अधिक पानी वाली नदियों को बाढ़ से बचाया जा सकेगा। महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री ने दमनगंगा-पिंजाल सम्पर्क में चार अंतर्राज्यीय सम्पर्क परियोजनाओं और समग्र आयोजना में पार-तापी नर्मदा सम्पर्क परियोजनाओं को शामिल करने का अनुरोध किया था। ये नदी सम्पर्क योजनायें नार-पार-गिरना, पार-तापी-गोदावरी, दमनगंगा (डकडारे) - गोदावरी घाटी सम्पर्क और दमनगंगा-वेतरणा-गोदावरी (कडवादेव) है। इन दो परियोजनाओं और महाराष्ट्र द्वारा सुझाई गई परियोजनाओं की जल, विद्युत लागत आदि की साझेदारी संबंधी समझौता ज्ञापन के मसौदे को सहमति के लिए महाराष्ट्र एवं गुजरात को भेज दी गई है।

मेरे संसदीय क्षेत्र दिन्डोरी को सिंचाई लाभ पहुँचाने वाली सम्पर्क परियोजनायें नार-पार-गिरना, पार-तापी-गोदावरी, दमनगंगा (डकडारे)- गोदावरी घाटी सम्पर्क और दमनगंगा-वेतरणा-गोदावरी (कडवादेव) को पूरा करने की जल, विद्युत लागत आदि की साझेदारी संबंधी समझौता ज्ञापन के मसौदे की सहमति महाराष्ट्र एवं गुजरात सरकार से शीघ्र प्राप्ति के लिए विशेष प्रयास किये जाये जिससे इन सिंचाई परियोजनाओं को शीघ्र क्रियान्वित किया जा सके।